(a2/1500/mmn-mkg)

Comment [m1]: Dr. Murli Manohar Joshi ctd.

And, in 1999-2000, he further observes:

> "The current value of the poverty line does not permit the poverty line class to consume the calories than the norm and the periodic price corrections that have been carried out to update the poverty lines are inadequate and indeed may be even inappropriate. Consequently, the poverty estimates made in the year after 1973-74 understate the true incidence of poverty in the country."

आपका सैक्रेटरी बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स का सैक्रेटरी बोल रहा है, जिसके आधार पर आप सारे आंकड़े लाते हैं कि वह नहीं होता है। फिर वह कहता है कि

> "Thus, there is a compelling case for re-estimating the poverty lines. The proportion of poor people living below the official poverty line declined from 56 per cent in 73-74 to 35 per cent in 93-94 and further to 28 per cent in 2004-05 whereas there has been no decline in the number of people consuming less calories than the norm. The set of food insecure in India is larger than the set of officially declared poor in India."

अब इसके बाद जो और असली की बात है determining the total number of BPL families. आप इण्डीविजुअल से फैमिलीज़ पर आ गये। उसकी बहस में मैं नहीं पड़ता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यह कहता हूं कि जब यह कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो उसमें जो प्लानिंग कमीशन के नुमाइन्दे थे, सरकारी अधिकारी, उन्होंने एक अपनी सिफारिश भेजी, वह क्या है?

> "We received a comment on our draft report from the distinguished member of the Expert Group representing Planning Commission suggesting that "the matter of fixing the percentage of people below poverty line is beyond the scope of the present Committee.""

पहले तो उन्होंने इस कमेटी पर ही यह कह दिया कि आप यह पावर्टी लाइन का स्कोप कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, इसका आपको अधिकार ही नहीं है।

> "It has been handled by a separate Committee headed by Shri Tendulkar. While the arguments given are plausible, it still remains in the domain of Tendular Committee which undoubtedly will consider all these issues raised."

यानि आपके तर्क तो ठीक-ठाक हैं, लेकिन अभी छोड़िये, तेंदुलकर इस पर आगे विचार कर लेंगे। तेंदुलकर कब विचार करेंगे, 2014 में। The report is expected to come in 2014, perhaps, after December elections.

"Needless to say, however, desirable it may seem…"

कितनी अच्छी बात आगे कह रहे हैं, उसको गौर से सुनिये।

"Needless to say, however, desirable it may seem, fixing the percentage at 50 per cent will still be considered arbitrary. It also has tremendous financial implications."

असली बात यह है। गरीबों की तादाद तो 50 परसेंट है, लेकिन उनको भोजन देने, उनको सुविधा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा है, कारपोरेट हाउसेज़ को 5-5 लाख रुपये की हर साल रेवेन्यू फोरगोन करना।...(व्यवधान) हां, पैसा है न, तभी तो आप उनको दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए पैसा नहीं है। फिर आगे सुनिये-

"It also has tremendous financial implications and once granted cannot be reduced."

अगर एक बार आप मान लेंगे कि 50 परसेंट है तो फिर उसका घटाना बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

"As such, it was recommended that 20 per cent variation may be allowed, which will bring up the poverty figure to approximately 35 per cent."

यानि आप घटा दीजिए, आपने 50 परसेंट कहा है, 20 परसेंट तो प्लस-माइनस हो ही सकता है। इसलिए 50 के बदले इसे 35 कर दीजिए।

"It shall be better to stick to the figure of 35 per cent and amend it upwards if Tendulkar Committee comes up with a figure which is higher."

यानि आप ऐसी बात कर रहे हैं, बी.पी.एल. की फीगर्स के साथ, गरीबों की संख्या घटाना-बढ़ाना, उसको मैनीपुलेट करने का हक आप अपने पास ही रख रहे हैं। अब आप देखिये, कमेटी क्या कहती है-

"We beg to differ with the above contention. Terms of reference for our Group were decided in consultation with the Planning Commission. These specifically mandate the Group to look at the relationship between estimation and identification of poor an issue, of putting a limit on the total number of BPL families to be identified."

आपने उनको टर्म्स ऑफ रैफरेंस दी, वे जब सही बात कह रहे हैं, जब वे हकीकत बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यह मत बताओ भइया, खर्चा बहुत होगा, लेकिन हमें कुछ तो करना है। आखिर चुनाव के लिए लोगों के सामने जाना है,

(b2/1505/cp/vr)

इसलिए पचास मत रखो, इसे पैंतीस पर ले आओ। अगर तेंदुलकर साहब कहेंगे कि यह पैंतीस नहीं है, चालीस है, तो चालीस है। आप गरीबों के साथ इस तरह की हेराफेरी क्यों कर रहे हैं? जो मुल्क की हकीकत है, उसे आप देश के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर आप लोगों से साफ-साफ कहें, सदन से कहें, सारे देश से कहें कि हकीकत यह है, आओ मिलकर रास्ता निकालें तो शायद रास्ता निकल सके। लेकिन आप यह दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ आप और आप हिंदुस्तान के गरीबों के मददगार हैं और बाकी सब लोग उनकी चिंता नहीं करते हैं।

मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ जैसी छोटी स्टेट नब्बे परसेंट लोगों को खाना दे रही है। वह चिंता उसको है, उसको असलियत मालूम है, वह हकीकत के साथ बात कर रही है, तमिलनाडु की सरकार दे रही है, गुजरात में बहुत लोगों को दिया जा रहा है, और भी राज्य हैं जहां बहुत से लोगों को ये चीजें दी जा रही हैं। ...(व्यवधान) पंजाब और मध्य प्रदेश हैं, ये तमाम सरकारें हैं जो अपने यहां गरीबों की असली संख्या को जानकर उनको ये चीजें दे रहे हैं। ...(व्यवधान) तमिलनाडु यूनिवर्सल दे रही है, मैंने कहा। आज सवाल यह है कि जब ये राज्य दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ दे सकता है, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? आप जिन चीजों पर खर्च करना चाहते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज को उसके बारे में पहले तय करिए, तब फिर यह बात होगी।

आप देखें कि हमारी हालत क्या है? दुनिया के ग्लोबल इंडेक्स के बारे में देखें। एक रिपोर्ट आयी थी, उसके एक सदस्य मिस्टर साईं नाथ कहते हैं, He says:

> "An astonishing amount of discussion on the subject of BPL in almost all platforms finally gets reduced to: how do we exclude people? How to prevent leakage? Complex criteria are drawn up to achieve this. Some get greatly exercised over the 'undeserving' poor claiming BPL benefits."

वह कहते हैं कि बहुत से अनडिजर्विंग गरीब हैं, जो बीपीएल में क्लेम करना चाहते हैं। वे कौन से अनडिजर्विंग गरीब हैं?

> "Poverty-free Dharavi: The last time such an exercise was put to use by Government. Dharavi, perhaps the biggest slum in the world and

Comment [M2]: Cd by b2

Comment [p3]: डॉ. मुरली मनोहर जोशी जारी

with a population of over a million, ended up home to just 141 BPL card holders."

दस लाख की आबादी में सिर्फ 141 बीपीएल होल्डर्स वहां रहते हैं। अगर यह गरीबी की हालत है तो फिर हिंदुस्तान में सारे ही अमीर हैं। गृह मंत्री जी आपके राज्य की बात है। धारावी, 141 बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं। ये आपकी गिनतियां हैं। ये दस लाख में से हैं। ...(व्यवधान) लोग कहते हैं कि बीपीएल कार्ड का मिसयूज हो रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। How serious would be such a misuse? How many of the better off would stand in queues for rice for Rs.2 a kilogram?

अगर हममें से कोई आदमी दो रूपए प्रति किलोग्राम खरीदने के लिए लाइन में लगता है, तो वह वाकई गरीब है, फिर तो उसको जरूरत है भाई। अगर उसको दो रूपए प्रति किलोग्राम खरीदना है और वह गरीब बनकर वहां जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि वह वाकई गरीब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। It is not possible.

आप ही की बनायी हुयी कमीशन है, अर्जुन सेन गुप्ता आप ही के सदस्य थे। Again, I quote it from his Report:

"In a country where 836 million people get by on less than Rs.20 a day, how many 'undeserving' poor would there be who would want to 'misuse' it? India ranks 66th amongst 88 developing nations in the Global Hunger Index of the International Food Policy Research Institute, that is, just one notch above Zimbabwe which has seen food riots."

आप सिर्फ जिम्बाबवे से एक ऊंचे हैं, जिंबाबवे में उसी साल फूड राइट्स हुए थे, तो वह कहते हैं कि आप जरा गौर कर लीजिए, आपकी हालत किसके साथ है। Even Bhutan and Nepal are higher than us.

"We also rank 132 in the United Nations Human Development Index, that is, one rung below Bhutan."

यह इस देश की हालत है। आप यहां गरीबों की गिनती को ठीक नहीं करना चाहते हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि गरीब घटते चले जा रहे हैं, गरीबों की संख्या कम होती चली जा रही है। हकीकत ऐसी नहीं है।

Economic Survey of Maharashtra for 2008-09 shows that the number of people below the official poverty line has been steadily growing even as its dollar billionaires have proliferated. वहां पर खरबपतियों की संख्या वह भी डॉलर में बढ़ रही है और उसी अनुपात में वहां गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है। यह है हिंदुस्तान की अमीरी और गरीबी का नक्शा। (c2/1510/san-raj)

Comment [p4]: cont by c2.h

Comment [l5]: cd

एक तरफ ...(व्यवधान) हां, वह तो है। रुपया उस मात्रा में धट रहा है, जिस मात्रा में गरीबी बढ़ रही है। कहते हैं कि it has now the third highest number of poor in the country in absolute terms ahead of only Uttar Pradesh and Bihar. Over the years the State has steadily excluded more and more people from PDS-BPL access. ये नतीजा है। आपने धारावी में 10 लाख आदमियों में से सब को बाहर कर दिया और 141 वहां बचे। यहा क्या है? गरीबी घट रही है। मुझे याद आता है, जब मैं अध्यापन करता था, यह सवाल उठा कि कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रों की फेल होने की संख्या ज्यादा है, तो एक प्रपोजल यह दिया गया कि आप पास मार्क को घटा दीजिए। ...(व्यवधान) मार्क्स 40 परसेंट से 33 परसेंट कर दीजिए, 33 परसेंट से 25 परसेंट कर दीजिए, तो पास वालों की संख्या बढ़ जाएगी। ...(व्यवधान) इसी तरह से पॉवर्टी लाइन का जो बेंच मार्क है, उसे नीचे कर दीजिए, तो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। कंजम्पशन कम कर दीजिए, कैलोरी इंटेक कम कर दीजिए। अब आप कहने लगे कि 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी का नॉर्म्स ठीक नहीं है, इसको घटाइए, तो ठीक है, आप इस सीमा रेखा से ऊपर निकल ही जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? कोई परेशानी नहीं है। हमें दुःख होता है, तकलीफ होती है, अफसोस होता है कि हम इस पार्लियामेंट में देश के सामने सच्ची बातें नहीं रखना चाहते, सच्ची तस्वीर नहीं रखना चाहते।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को इस बारे में दिशा-निर्देश दीजिए, संकेत दीजिए। इस सदन में देश की हकीकत सामने आनी चाहिए। रास्ते निकलने चाहिए। भूख केवल किसी एक पार्टी की नहीं है। भूख केवल किसी एक समाज की नहीं है। भूख केवल किसी एक राज्य की नहीं है। भूख बड़ी खतरनाक चीज है। भूख ऐसी खतरनाक चीज है कि जब भूख की ज्वाला पेट में उठती है, तो फिर इस संसद की दीवारों पर उसका असर आता है। मैं बिल्कुल विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप देखिए, आप ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए है। आज आप अनाज की बात कर रहे हैं। आपकी अनाज की पैदावार क्या है? मैं आपको बताऊं। आपके अनाज की पैदावार है - वर्ष 2012-13 में कुल खाद्यान्न 255.36 मिलियन टन हुआ है, जिसमें 104.22 मिलियन टन धान था, 92.46 मिलियन टन गेहूं था, मोटा अनाज 40.6 मिलियन टन था और दलहन 18.45 मिलियन टन था। ये कुल मिला कर

255.36 मिलियन टन है। ...(व्यवधान) आप के देश की आबादी 1 अरब 20-25 करोड़ है। उसके हिसाब से सिर्फ 218 किलोग्राम परकैपिटा, पर इयर है।

कृषि मंत्री जी आपके विभाग में कानून है - फेमिन कोड ऑफ इंडिया, अपने सेक्रेट्री से कहिए कि इसे करे। वर्ष 1860 का बना हुआ फेमिन कोड कहता है कि 200 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति थ्रेशहोल्ड ऑफ फेमिन। अगर इससे कम हुआ तो अकाल। यह मिनिमम है। आप के देश में संतुलन बनाए रखने के लिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। परकैपिटा अनाज के मामले में, जहां आप वर्ष 1947 में थे, आप आज वहीं हैं। किसानों की मेहनत के लिए सारे देश को अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने बढ़ती हुई आबादी के साथ, अधिक अनाज पैदा कर खाना खिला दिया। लेकिन यह हमारे और आपकी वजह से नहीं हुआ। हम तो वहीं हैं। हम कितना ही शोर मचाएं कि हमने देश में इतना अनाज पैदा कर दिया, That is despite of us and despite of you. किसान ने अपनी मेहनत से अपने-आप को भूखा रख कर, आत्म हत्या कर के हमको भोजन दिया है, इसको समझिए। आप इस देश की बात कर रहे हैं। इस देश के शास्त्रों ने, उपनिषद् ने, पुराने ऋषि-मुनियों ने आदेश दिया था, अन्नम बहुकुर्वी, बहुत अनाज पैदा करो। अन्नाज इसलिए बहुत पैदा करो, ताकि मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंग, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कबूतर और चिड़िया खाएं। सब का नाम ले कर, वे कहते हैं। यह हमारे तैतरीय उपनिषद् का वाक्य है। वे क्या कहते हैं, इसको समझिए। आप किस देश के निवासी हैं? The next and the last *anuvak* of the Upanishada is resplendent with respect for *ann*, with the discipline of offering *ann* to all those who arrive at the door, at the doorstep of the society, of the Government and with descriptions of the joy and bliss of the one who follows that discipline. (d2/1515/nsh-ak)

Comment [S6]: Contd by D2

Comment [n7]: Dr. Joshi cd

यानी भोजन सबको दीजिए, कोई भूखा न रहे। आगे चलकर वे कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी राज्य में अगर कोई व्यक्ति, वह बच्चा जो टुकुर-टुकुर देख रहा है कि लोग सामने भोजन कर रहे हैं, सुस्वादु भोजन कर रहे हैं, चटखारे लेकर भोजन कर रहे हैं और यह बच्चा केवल देख रहा है। वह कहता है ऐसे राज्य को नष्ट हो जाना चाहिए जहां के बच्चे दूसरों को खाते हुए देखकर अपने पेट की ज्वाला से संतुष्ट नहीं हो सकते।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी देश ऐसा नहीं रहना चाहिए। आगे चलकर उन्होंने और बात कही है कि किसी देश में कोई छात्र भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा भूखा रहता है तो वह कहता है कि उस राजा को जीवित रहने का अधिकार नहीं है।...(व्यवधान)

चिदम्बरम जी यहां उपस्थित नहीं हैं। वे अक्सर तिरुवल्लूवर को कोट करते हैं।...(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : वे यहां उपस्थित हैं।...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): मेरा उनसे भी निवेदन है कि वे पढ़ लें।

It says that : "Wretched is the man of poverty who begs, more wretched is he who merely closes the door on the hungry and feeds no one."

फिर उपनिषद कहता है कि जो अकेला खाता है, वह पापी है। दूसरे को बिना खिलाए, दूसरे को भूखा रखकर जो खिलाते हैं...(व्यवधान) सवाल यह है...(व्यवधान) आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपस्तम्ब ने क्या कहा था। वर्ष 2001 में एग्रीकल्चर पर साइंस कांग्रेस थी। मैं साइंस मिनिस्टर था। मैंने जो अपना भाषण समाप्त किया था, उसमें आपस्तम्ब को कोट किया था। वह कहता है --

नवाश्यबिशेत् सुधारोगेण,
हिमतापाभ्याम वावशिदभेव,
बुद्धिपूर्वाकश्चित्।

It means that : "Let no one should suffer from hunger and disease, or from extremes of heat and cold. No one in the Kingdom ought to suffer thus, either because of the general scarcity or because of specific design against him."

आप दोनों काम कर रहे हैं - आप स्केयरसिटी पैदा कर रहे हैं और एक डिजाइन भी पैदा कर रहे हैं। आप नीतियां ऐसी बना रहे हैं कि इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब और भूखी रहे। वह डिजाइन नहीं है। आप उनके बाद उनको लालच दिखाकर, उनके सामने सारा बिल पेश करके, उनको लुभाकर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि आप भूखे थे, हम आपको दे रहे हैं। जी नहीं, यह आपका कर्तव्य है। हम और आप जो आज यहां संसद में बैठे हैं, हम सबका कर्तव्य है। मैं यह नहीं कहता कि इस संसद का कर्तव्य है। हां, अगर उन्होंने भूखे किए हों, तो हम कोशिश करेंगे कि भूख मिटाएं, मिलकर कोशिश करेंगे। इसे समझ लीजिए।

आगे देखिए, बहुत मजेदार-मजेदार बातें कहते हैं। आपने बिल में कहा कि किसानों के लिए आपको बड़ी हमदर्दी है। क्या कहने, इतनी हमदर्दी।...(व्यवधान) सैक्शन 31 में इन्होंने प्रोविजन्स दिए हैं जिनका उल्लेख शैडयूल 3 में किया गया है।

It says : "Revitalisation of Agriculture – (a) agrarian reforms through measures for securing interests of small and marginal farmers."

कितनों का इंटरस्ट तय कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हालत क्या है? मार्जिनल फार्मर कहां जा रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि हिन्दुस्तान में ढाई हजार किसान हर रोज खेती छोड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी, यह आपका विभाग है। मैं सब राज्यों की सरकारों से, देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ढाई हजार

किसान प्रतिदिन खेती छोड़ रहे हैं। वह मार्जिनल फार्मर है, वह मजदूर बन रहा है। आप कहते हैं कि स्माल और मार्जिनल फार्मर के लिए कुछ इंतजाम करेंगे। कहां है इंतजाम? आप उसके लिए क्या करेंगे? शब्दों में बहुत अच्छा लगता है। अरे, मार्जिनल फार्मर। प्रधान मंत्री जी अक्सर शेर कहते हैं। उसके लिए आप यही कहो। वह बेचारा यही कहता है - साहिल के तमाशायी किसान पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं। साहिल के तमाशायी हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। यहां किसान डूब रहा है, मार्जिनल फार्मर डूब रहा है।

(e2/1520/rjs-sh)

Comment [n8]: Cd by e2

Comment [r9]: Dr. Murli Manohar Joshi-cd

उनकी आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि संख्या समाप्त हो गयी है। क्या आप रोक रहे हैं? क्या आप उसे खेती का उचित दाम दे रहे हैं? क्या आप उसे ठीक से एमएसपी दे रहे हैं? इस लॉ में आगे चलकर जो प्रावधान हैं, आप एमएसपी किस हिसाब से देंगे या लेंगे, उसकी बात साफ नहीं होती। मुझे अफसोस है और कभी-कभी चिन्ता होती है कि कहीं इस बिल के तीन साल बाद आप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं न करने लग जायें, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि तब आप उधर नहीं होंगे, कोई और होगा। ...(व्यवधान) लेकिन ये ऐसे इंतजाम क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हिन्दुस्तान में खेती का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी घटती जा रही है। एक साहब ने मुझसे कहा कि अरे साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका में खेती का जीडीपी में सिर्फ चार परसेंट कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैंने कहा अमेरिका में एग्रीकल्चर का उनकी इकोनॉमी में 60 परसेंट कंट्रीब्यूशन है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर बीमा है और दस प्रकार के धंधे उसके साथ चलते हैं। उन्हीं की अपनी इस बारे में स्वीकारोक्ति है कि sixty per cent of American economy is based on their agriculture. हिन्दुस्तान में अगर आज हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का 15 परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तो इस रफ्तार से शायद 90 परसेंट हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का असर होना चाहिए। हो सकता है, मगर आपने इसमें लिख दिया कि हम यह करेंगे। क्या करेंगे आप? उनके लिए स्टोरेज बनायेंगे। कब बनायेंगे? दस-बारह साल में तो अभी तक बने नहीं। उसके पहले भी तीस-चालीस आप रहे, तब भी नहीं बने। हम भी छः-सात साल रहे, तब भी नहीं बने। ईमानदारी की बात करें, तो बहुत बन गये। क्यों नहीं बन रहे? आप फूड चेन क्यों नहीं बना रहे? आप अपने बजट्स को देखिये, अपने इन्वेस्टमैंट्स को देखिये। स्टोरेज क्यों नहीं बना रहे? वेस्टेज क्यों हो रहा है? आज हालत यह है कि मुझे कृषि रिसर्च के अनुसंधान जरनल में पढ़ने को मिला कि हिन्दुस्तान से जो अनाज एक्सपोर्ट होता है, वह सिर्फ वहां बीयर बनाने के काम में आता है, वह खाने के काम में नहीं आता। क्यों नहीं हमारी खेती का, यह वह देश है जो खेती से कितना अधिक काम कर सकता है। आज भी कर सकता है। आपकी 57 से 60

परसेंट जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप उन्हें क्या चीजें दे रहे हैं? आपने लिखा है, ...(व्यवधान) फिर कहते हैं --

> "Giving top priority to movement of food grains and providing sufficient number of rakes for this purpose."

कहां है रैक्स? कौन कम्पनी यहां रैक बना रही है, रेल मंत्री जी? ...(व्यवधान) कितने रैक्स आप एक्सट्रा बनवायेंगे अरबों-लाखों टन अनाज को लोड करने के लिए। कितने साल में बनेंगे, कौन कम्पनी बना रही है? रैक्स बना देंगे, हवा में। आप कहेंगे कि आजा रैक और हाथ में आ गया रैक। वह काला जादू आपके यहां होता है गृह मंत्री जी। शायद उसी काले जादू से आप रैक बनाकर देंगे। कौन से रैक बना रहे हैं? आप उसका क्या कर रहे हैं?

हैल्थ केयर -- हम जानते हैं कि हैल्थ केयर कैसी है। पीएसी की कमेटी में सीएजी ने हैल्थ केयर की जो रिपोर्ट दी थी, मुझे मालूम है कि क्या थी हैल्थ केयर? Where is the healthcare? मैंने अपने जिले बनारस में अभी परसों जिला समिति की समीक्षा की। Healthcare was the poorest. ...(व्यवधान) अस्पताल नहीं है, डाक्टर नहीं हैं, तीन-तीन साल पुरानी दवाइयां हैं। गिरिजा जी भी कह रही हैं कि हां, सही है। अब बताइये। फिर कहते हैं कि "Nutritional health and educational support to adolescent girls." कितनी और कहां? "Adequate pensions for Senior Citizens". What is this 'adequate"? 300 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया। आप क्यों ऐसी बातें लिख रहे है, जिसे देखकर किसी को विश्वास हो ही नहीं सकता। आप फिर कहते हैं कि "Geographical diversification of procurement operations." कितने साल में करेंगे? कितना होगा? आप डिस्ट्रिक्ट-डिस्ट्रिक्ट में अगर चाहें, तो प्रोक्योर करके बंटवा सकते हैं। हमारे देश में होता रहा है। आप कोई ऐसी बात तो कहिए, जिस पर यकीन होता हो। फिर आप देखिये। मैं आपका बता रहा हूं। शरद जी का लेख है, जो आपने बिजनस लाइन में लिखा है। आप कहते हैं कि --

> "Farm size, given that India has the largest number of poor and malnourished people in the world, increasing food supply is paramount to achieving inclusive growth. Since agriculture forms the resource base for a number of agro-based industries and agro-services, agriculture should not be viewed only as a farming activity, but part of a wider value chain."

Comment [r10]: Fd by f2

(f2/1525/vb/smn)

Comment [MSOffice11]: Cd. Dr. Murli Manohar Joshi

आप फार्म साइज़ बता रहे हैं, दो हेक्टेयर, ढाई हेक्टेयर, 1.23 हेक्टेयर, 2.26 हेक्टेयर। यह 1970-71 में हो गया। 4 हेक्टेयर और उससे ऊपर वाले को आप छोटा किसान कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? किसान की हालत क्या है? मुलायम सिंह जी, देखिए आप समर्थन मत कीजिए इसे, यह मेरा आपसे अनुरोध है। यह किसान विरोधी है। यह किसान की तरफ ध्यान नहीं देती, सिर्फ लोक-लुभावन नारे लगाती है। Farmer's suicides rate soar above the rest. यानी गिनती लिपटती चली जा रही है। अब इसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक और समस्या आएगी, अगर आप खेती क्षेत्र का उपभोग करेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक में भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या हिन्दुस्तान में 20 करोड़ बताई। यह गरीबी नहीं है, भूखमरी है। यह भी बताया गया कि पिछले 15 सालों में तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। फिर वे यह भी कहते हैं कि अमेरिका तो हर जगह अपने किसानों की हित की बात कहता है, आप नहीं करते यानी हमारा देश नहीं करता। वर्ष 1996 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि 2015 तक, अभी दो वर्ष बाकी हैं, गांव छोड़कर भारत के जितने लोग विभिन्न शहरों में बसेंगे, उनकी कुल जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगुनी होगी। अभी इन तीन देशों की जनसंख्या 20 करोड़ थी, अब 40 करोड़ जनसंख्या हिन्दुस्तान के शहरों में बसेंगे, तो अब आप बताइए इनको रोज़गार दे सकेंगे आप! ये रोज़गार तो आपको छोटे खुदरा व्यापार में, किसानी में और एस.एम.ईज़ में मिलते हैं। उनको आप नष्ट करते जा रहे हैं। उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है और आप ऐसा बिल ला रहे हैं। इसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। 166 ग्राम अनाज़ प्रतिदिन में इस देश का कोई आदमी अपनी भूख नहीं मिटा सकता। यदि उसका कंजम्पशन 10 किलोग्राम है, तो बाकी कहां से खरीदेगा?...(व्यवधान) आपको क्या चिन्ता है? आपकी ही बात कर रहा हूं। आप चिन्ता मत कीजिए। ...(व्यवधान) इस पर ज़रा ध्यान देने की जरूरत है। यह आवश्यक है। मैं फूड सिक्योरिटी के पक्ष में हूं। क्यों? क्योंकि अमेरिकन फूड सेक्रेट्री ने एक बात कही थी, जब से मैंने उसे पढ़ा है, तब से मैं फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा चिन्तित हूं। उन्होंने कहा था कि "Food is an important weapon and we can use it for negotiation". अमेरिकन फूड सेक्रेट्री ने आज से 25-30 साल पहले यह बात कही थी कि अनाज़ हमारे झोले में एक बहुत महत्त्वपूर्ण हथियार है। इसका उपयोग हम गरीब देशों के साथ पॉलिटिकल बारगेन करने में करेंगे।

अध्यक्ष महोदया, वह देश वहीं तक आज़ाद है, जहां तक इसका फूड आज़ाद है। देश जितना फूड सिक्योर है, उतने ही उसके बॉर्डर भी सिक्योर होंगे, उतने ही उनकी इकोनॉमी भी सिक्योर होंगी, उतना ही उसका रुपया भी सिक्योर होगा। अगर आप फूड सिक्योरिटी शत-प्रतिशत लोगों को नहीं दे सकते, अगर

आप हिन्दुस्तान के किसान की टैलेंट का, उसकी मेहनत का पूरा उपयोग नहीं कर सकते और वाज़िब तौर पर उसकी मदद नहीं कर सकते, तो यह फूड सिक्योरिटी बिल महज़ क़ागजी रह जाएगा। ...(व्यवधान) आपके पास पैसे कितने हैं, यह भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप आगे आने वाले समय में इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, बजट में कितना प्रावधान करेंगे? कैसे करेंगे? हम जानना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इस देश को अन्न सुरक्षा के मामले में पूरे तौर पर सुरक्षित करने के लिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं देश को सुरक्षित देखना चाहता हूं। हमारी पार्टी इस देश को ही नहीं दुनिया के हर भूखे को खाना देना चाहती है। हम दुनिया के हर कीट-पतंग को, पशु-पक्षियों को खाना देना चाहते हैं। कोई भूखा न रहे। हम उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारे किसान में इतना दम है, इतनी हिम्मत है। मगर आपका बिल कुछ नहीं बोलता है। यह सिर्फ साढ़े तीन छटांक अनाज़ देने को कहता है। यह कहता है कि हमने गाड़ी ठीक कर दिया, हमने फूड सिक्योरिटी कर दी। क्या किया? कुछ नहीं। महिलाओं के लिए तो वह एडोलसेंट स्कीम चल ही रही है। आप बच्चों के लिए कहते हैं, तो आप अक्षय पात्र योजना को क्यों नहीं स्वीकार करते? Fully fortified food and untouched by human hands, cooked, packed in packages, transmitted by belt- टैक्नोलॉजी है, मैंने शुरू करायी थी अक्षय पात्र योजना। (g2/1530/rps-sr)

Comment [MSOffice12]: Cd. by g2

Comment [A13]: Dr.Joshi cd.

आज दस लाख बच्चों को भोजन दे रहे हैं। थोड़ा सा पैसा खर्च करने की जरूरत है। जनता पैसा देती है उसके लिए। आप चलाइए योजना, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम देने को तैयार हैं। लोग काम करने के लिए तैयार हैं, आप उत्साहित तो कीजिए। आप सिर्फ अनाज देते हैं, लेकिन हर बच्चे पर दो रुपये 27 पैसे जनता से चन्दा लेकर बनाते हैं। किसी टीचर से खाना नहीं बनवाते। सेंट्रलाइज्ड तरीके से खाना बनकर, अनटच्ड बाई ह्युमन हैण्ड्स, मशीन से सब्जी कटती है, मशीन से ही अनाज धुलता है, स्टीम्ड कुकिंग होती है, डिब्बों में पैक होता है, बस में रखकर स्कूल तक जाता है। हम ले गए थे, तब हमारे राष्ट्रपति थे श्रीमान अब्दुल कलाम साहब, उनको इसे देखकर हैरत हुई और वे सबको मिलकर आए। उसका भी मैं विशेष गुण बताता हूं, वह मंदिर की योजना है - अक्षयपात्र । स्कूलों में जाते हैं, वहां हर सम्प्रदाय के बच्चे रहते हैं। ...(व्यवधान) मथुरा में है। आप उसे आगे चलाइए।...(व्यवधान) लेकिन वहा वे लेते हैं। जो मुस्लिम सम्पद्राय के बच्चे हैं, उनको मालूम है कि यह मंदिर का प्रसाद है, वे उस प्रसाद को लेते हैं और फिर बिसमिल्लाह उर रहमानो रहीम करके खाते हैं। सब खाते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? आप लीजिए उस स्कीम को। आप छत्तीसगढ़ की स्कीम को लीजिए। आप हिन्दुस्तान के किसान को मजबूत कीजिए, हम उसमें मदद करेंगे। किसान के लिए जो कुछ करना चाहेंगे, अगर वह वाजिब होगा, राजनीति से परे होगा,

तो हम आपकी मदद करेंगे। देश को अन्न के मामले में सुरक्षित करने की हर कारगर योजना की, पोलिटिकल योजना की नहीं, चुनावी योजना की नहीं, लेकिन जो भी ऐसी योजना होगी, उसका हम पूरे तौर पर समर्थन करेंगे, उसको ले जाएंगे। इस कानून की तमाम खराबियों को आप दूर कीजिए। खाद्य मंत्री जी, इस तरफ ध्यान दीजिए कि आपके बिल में कितनी खामियां हैं। बहुत सी उन्होंने बताई हैं, बहुत से अमेंडमेंट्स हैं, मैं उन पर नहीं बोल रहा हूं, वे इस बात के सूचक हैं कि लोगों की इसमें रुचि है। मेरे पास रोज लोगों की चिट्ठियां आती हैं कि इसमें यह प्रावधान चाहिए, यह सुधार चाहिए, अच्छा होगा कि आप इस बिल को फिर से सुधारें, सुधारने के बाद फिर से लाएं। कोई हर्जा नहीं होगा, क्योंकि आपने आर्डिनेंस के मार्फत काम शुरू कर ही दिया है। आपको प्रचार का जितना लाभ लेना था, आप ले चुके हैं, अब ज्यादा लाभ तो मिलेगा नहीं।...(व्यवधान) मेरा अनुरोध है आपसे कि इसको ठीक कीजिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। हमारी पार्टी के लोग देश के हर आदमी को भोजन, पौष्टिक भोजन से युक्त, हृष्ट-पुष्ट देखना चाहते हैं। ऐसा देखना चाहते हैं कि भारत का जवान जहां जाए, लोग कहें कि ये आ रहा है पट्ठा, जो देश की रक्षा करेगा, दुनिया की रक्षा करेगा, भूख और गरीबी से दुनिया को बचाएगा।

(इति)

1533 बजे

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली): अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं। आज हमारे सामने एक एतिहासिक कदम उठाने का मौका आया है जिससे हम अपने गरीब भाई-बहनों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्ष 2009 के घोषणापत्र में देश से वायदा किया था कि हम खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे, सभी देशवासियों को, खासकर कमजोर वर्गों को पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराएंगे। आज अपनी पार्टी की तरफ से मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी है कि हम इस वायदे को निभा रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे समाज के अनेक वर्गों को समृद्धि का लाभ मिला है, जो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, लेकिन हमारे सामने जो सवाल है, वह उन तबकों का है, जो उतने भाग्यशाली नहीं हैं और जो इस समृद्धि की पहुंच से दूर रहे हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल है - हमारी जिम्मेदारी क्या है? उन लोगों के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी क्या है, जो दूसरों के मुकाबले कम भाग्यशाली हैं? उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वे आज भी भूख और कुपोषण का शिकार होने के लिए अभिशप्त हैं।

(h2/1535/jr-kmr)

Comment [A14]: cd.by h2

Comment [j15]: Smt. Sonia Gandhi cd.

अध्यक्ष महोदया, आज सदन के सामने एक बड़ा संदेश देने का अवसर आया है देश और दुनिया के लिए, एक ऐसा संदेश जो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल ठोस है कि भारत अपने सभी देशवासियों की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। आज सदन के सामने यह सुनिश्चित करने का अवसर आया है कि हमारे देश का हरेक बच्चा कुपोषण से मुक्त होकर बड़ा हो। उसकी क्षमता का विकास हो और वह अपने देश की भावी समृद्धि में अपना हाथ बंटाए। आज सदन के सामने एक ऐसा अवसर आया है जब हम उन सब लोगों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार दे रहे हैं, जिन्हें उसकी जरूरत है। आज सदन के सामने एक ऐसा अवसर आया है जब हम उस गलती को दूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की मानव क्षमता की हर साल बेहिसाब बर्बादी होती है।

अध्यक्ष महोदया, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए साधन हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सवाल साधनों का नहीं, हमें इसके लिख साधन जुटाने ही होंगे। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यह किया जा सकता है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सवाल यह नहीं कि क्या हम यह कर सकते हैं या नहीं, हमें यह करना ही है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यह बिल किसानों के हित में है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कृषि और किसान दोनों ही हमारी नीतियों के प्रमुख अंग हैं। उनकी जरुरतों को हमेशा सबसे ऊपर रखा था और आगे भी रखेंगे। इसी के साथ हमें पूरा एहसास है कि अभी तक जो हमारी आर्थिक विकास दर थी, उसे फिर से हासिल करना भी जरूरी है।

अध्यक्ष महोदया, पीडीएस और सस्ते अनाज की दुकानों के बारे में हम सब जानते हैं। इस समय ऐसी दुकानों की तादाद पांच लाख से भी ज्यादा है। देश के कुछ हिस्सों में ये ठीक से काम करती हैं, कुछ में नहीं भी करतीं। कुछ हिस्सों में इनकी पहुंच बहुत अच्छी है, कुछ में नहीं भी है। पीडीएस में सुधार की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ सही मात्रा में, सही लोगों तक पहुंच सके। इस प्रणाली में कुछ इलाकों में लीकेज की समस्या बहुत ही ज्यादा है और इसे दूर करना ही होगा। यह इस कानून की सफलता के लिए बुनियादी जरूरत है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्यों में पीडीएस सही ढंग से लागू हो। यही वजह है कि इस बिल में पीडीएस प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रावधान शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदया, कानूनी तौर से खाद्य सुरक्षा का अधिकार अपने आपमें जरूरतमंदों को सशक्त बनाने का, प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने का, भ्रष्टाचार को कम करने का और व्यवस्था को प्रभावी बनाने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। मुझे खास खुशी इस बात की है कि यह बिल महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों को पीडीएस चलाने की भागीदारी देगा। साथ ही आगे चलकर आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी और दोहरे राशन काड्र्स खत्म होंगे।

Comment [j16]: cd.by j2

Comment [l17]: Cd by Sonia

(j2/1540/har/vp)

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बिल में अंत्योदय परिवारों के हित भी पूरी तरह सुरक्षित हैं और आईसीडीएस, मिड-डे मील योजना जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम भी इस बिल के अंग हैं। लेकिन हमें यह भी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि इन योजनाओं में कई प्रकार की कमियां हैं। यदि इसमें प्रतिबद्धता और ईमानदारी नहीं होगी तो जनता के प्रति घोर अन्याय होगा और उनकी उपेक्षा घातक होगी। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों कार्यक्रम पूरी दुनिया में बेमिसाल हैं। दस करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगभग 12 लाख प्राइमरी स्कूलों में रोजाना भोजन दिया जाता है, लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनसे 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को सेवा प्राप्त होती है। फिर भी हमें इन सेवाओं की कमियों को दूर करना ही होगा और ये काम हम सबको मिलकर करना है, खासकर राज्य सरकारों को जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। स्थानीय जवाबदेही सख्ती से लागू की जानी चाहिए।

Madam Speaker, before I conclude, allow me a few moments to look back a little. Under the leadership of the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh Ji, our UPA Government, in 2005, brought in the Right to Information law. That has ushered in an unprecedented transparency in public life, sometimes, to our own

disadvantage. A little later that year, the Right to Work, Mahatma Gandhi NREGA became a reality. This has provided employment to one in four rural households in the past seven years and has led to increased-rural wages. In 2006, the path-breaking Forest Rights Act came into the Statute Book. This has benefited lakhs of tribal and other families who have traditionally relied on forest for their livelihood. In 2008, the Right to Education came into being. This has already led to a sharp increase in enrolment in schools.

The Food Security Bill is thus the fifth in a series of what might be called 'our wise-based approach'. This approach provides legal entitlements to people, puts pressure on the Executive to be more responsive and accountable, and also puts in place credible mechanism to redress grievances. This approach, I believe, is bringing about an empowerment revolution in our country – something we are proud to have facilitated.

Madam Speaker, our goal for the foreseeable future must be to wipe out hunger and mal-nutrition from our country. This legislation is only a beginning. As we move forward, we will be open to constructive suggestions; we will learn from experience.

In essence, Madam Speaker, we have today, an opportunity to transform the lives of tens of millions of our people. I believe that we must, together, rise to the occasion, set aside our differences and affirm our commitment to their welfare and wellbeing.

It is my fervent hope and my humble appeal that we, as representatives of those very people, should convert this Bill into an Act and do so, unanimously. Thank you. (ends)

(k2/1545/ind-rk)

Comment [r18]: Fld by K2

अध्यक्ष महोदया : श्री मुलायम सिंह।

...(व्यवधान)

एक अन्य माननीय सदस्य : सोनिया जी ने लिखा हुआ भाषण पढ़ा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुझ से पूर्वानुमति ली गई थी और नियम 352 के अंतर्गत हमने अनुमति दी थी।

1545 बजे

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा बिल लाने से पहले देश के राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए था और मुख्यमंत्रियों की राय लेनी चाहिए थी। अगर मुख्यमंत्रियों की राय ली जाती तो आपके सामने अच्छे सुझाव आते और एक अच्छा बिल आता, लेकिन पूरी तरह से मुख्यमंत्रियों की उपेक्षा की गई है। इस बिल के आने से राज्यों पर बहुत बोझ पड़ेगा। राज्यों की परेशानी को बिना सुने यह बिल लाना गलत है।

अध्यक्ष महोदया, मैं अब भी कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे चार दिन के लिए रहे, हम लोग समर्थन तो करेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्रियों की राय ले कर इस बिल को लाना चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है। सारा बोझ राज्यों पर पड़ेगा। आपने गरीबों को किस आधार पर छांटा है? आपने 1997 के आधार पर छांटा है और अब 2013 चल रहा है। पिछले 16 सालों में गरीबों की संख्या में कितनी वृद्धि आई है या कमी आई है, इसकी कोई संख्या नहीं दी है। आपको संख्या बतानी चाहिए कि कितने गरीब हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का अभी तक पता नहीं है। जो असली गरीब हैं, उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। क्या आपने अंदाजा लगाया है कि इस बिल के कारण राज्यों पर जो आर्थिक बोझ पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है। राज्यों की कौन मदद करेगा, राज्य के पास धन कहां से आएगा और राज्य इस आर्थिक बोझ को कैसे सहन करेंगे? इसका उल्लेख कहीं भी इस बिल में नहीं है। 26 हजार करोड़ या 30 हजार करोड़ चाहे जितना भी बोझ हो, राज्य कैसे इस बोझ को उठा सकते हैं? कई राज्यों की आर्थिक हालत आज बहुत खराब है। आपने कानून बना दिया और राज्यों पर छोड़ दिया है। सारा बोझ तो राज्यों पर पड़ेगा। आप राज्यों को क्या दे रहे हैं, इसका उल्लेख कहीं भी बिल में नहीं है। आप खड़े हो कर बता दीजिए, तो मैं बैठ जाऊंगा। बिल में कहीं उल्लेख नहीं है कि आप राज्यों को देंगे।

इसी तरह से क्या इस बिल में कहीं किसानों की उपज खरीदने की आपने पक्की गारंटी दी है? यह सबसे गंभीर मामला है। किसान की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी कहीं बिल में नहीं है। न तो जमीन की गारंटी है, न खरीद की गारंटी है। यह कैसा बिल है? कृषि मंत्री जी, आप तो स्वयं किसानों की परेशानियां जानते हैं। इस बिल में किसानों की फसल की खरीद की गारंटी कहां है? आप बीच में बिचौलिया भी भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप गारंटी करें कि किसानों की उपज खरीदी जाएगी। आप बिल में सुधार कीजिए और संशोधन पेश कीजिए कि किसानों की फसल का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी। यह गारंटी इस बिल में नहीं है। किसान बरबाद हो जाएगा। यह बिल किसान विरोधी है।

इसमें आप संशोधन कीजिए। किस राज्य में कितनी सुविधा दी जाएगी, किसान को क्या दिया जाएगा, यह गारंटी होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में एक-सी सुविधा दी जाएगी। किसी राज्य को आप ज्यादा सुविधा देंगे और किसी राज्य को कम सुविधा देंगे। इस बिल में कहीं नहीं दिया गया है कि सभी राज्यों को एक-सी सुविधा दी जाएगी।

(l2/1550/asa/rc)

आज एक रुपया भी देने की स्थिति में नहीं है। उनको भोजन मुफ्त देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और हमने भी कहा था लेकिन उस वक्त आपने उनको मुफ्त भोजन नहीं दिया। यह इसी सदन में कार्रवाई में है और तब मैंने भी कहा था कि देना चाहिए, तब उस वक्त आपने नहीं दिया। तब गरीब आपको याद नहीं आए लेकिन जब चुनाव आ गया तो दे दिया। क्या चुनाव को सामने रखकर काम किया जाएगा? यह चुनाव के लिए है। यह सीधा-सीधा चुनाव के लिए है। कभी मनरेगा आ जाएगा। कभी खाद्य सुरक्षा बिल आ जाएगा। इसलिए केवल चुनाव पर ही दृष्टि है या क्या भूखे और गरीबों के लिए ही कुछ कर रहे हैं? यदि गरीबों के लिए ही करना होता तो 6 महीने पहले ही कुछ कर देना चाहिए था जब लोग भूख से मर रहे थे और रोजाना संख्या आ रही थी। महाराष्ट्र जैसे सूबे में भूख से मरने वालों की संख्या समाचार-पत्रों में आ रही थी, तब क्यों नहीं किया? जब लोग भूखों मर रहे थे तब तो दिया नहीं। जब गरीब लोग भूखों मर रहे थे और हम लोग यहां सदन में सवाल उठा रहे थे, शोर कर रहे थे कि लोग भूखों मर रहे हैं तब तो कुछ नहीं दिया। यह देश के लिए शर्म की बात है। तब यह बिल कहीं नहीं आया। अब केवल इसीलिए आया और सीधी सीधी बात है कि चुनाव आ गया, इसलिए बिल आ गया।

हर चुनाव में केवल एक मुद्दा बनाकर आप चुनाव में जाना चाहते हैं। इसमें गरीबों के लिए कहीं कुछ नहीं है। किसानों की जमीन को लेकर उत्पादन शुल्क की, उसकी उपज की खरीद की सौ फीसदी गारंटी करनी चाहिए। यानी उपज को खरीदने की पक्की गारंटी हो और गरीबों की संख्या स्पष्ट हो। सभी के लिए व्यवस्था हो। लेकिन कितने की व्यवस्था है? यह कहीं है ही नहीं कि कितनों को आप मुफ्त भोजन देंगे? कितने लोग भूखे हैं? यह संख्या कहीं है ही नहीं। इसमें अंदाज ही चल रहा है। यह अंदाजिया बिल है। यह सब होना चाहिए कि इतने प्रतिशत लोग गरीब हैं। इतने लोग फलां शहर में या फलां गांव में गरीब हैं और उस संख्या के अनुसार हम उनको देंगे। अब पता नहीं जाने किसको मुफ्त भोजन दिया जाएगा? सरकार बताए कि कौन सा आदमी गरीब माना गया है? किस आधार पर माना गया है और कौन सी सरकारी रिपोर्ट है? वह सरकारी रिपोर्ट कहां से आई है? किसी आधार पर ही गरीब माना जाएगा। देश के बीपीएल धारकों की गणना सही नहीं है। प्रधान मंत्री जी, पहले गणना कराइए। पहले गणना हो जानी चाहिए

Comment [i19]: cd.

Comment [a20]: ctd by M.Singh Yadav

और जब यहां गणना पर चर्चा होगी तो हम सारे दलों के लोग आपको सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन गणना की नहीं गई है और मुफ्त तथा सस्ता भोजन देना आप शुरु कर देंगे। अब हम क्या बोलें कि कौन वंचित रहा है? किसको मिल रहा है? यह बात किसी को पता ही नहीं है कि किसको भोजन मिल रहा है। यह सब अंदाजिया चल रहा है। खाद्य सुरक्षा में केवल बिल आ रहा है। राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह तो गारंटी आपको करनी पड़ेगी कि राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्यों पर किसान का बोझ पड़ेगा। अब राज्यों पर कितना आर्थिक संकट पड़ेगा? बिल में इस बारे में कहीं दिया ही नहीं गया है। इसका बोझ राज्यों पर भी पड़ेगा। यह बिल में है ही नहीं और वे राज्य कहां से पूर्ति करेंगे या केन्द्रीय सरकार उसकी भरपाई करेगी, यह बिल में कुछ बताया ही नहीं गया है। यह बिल आपने दिखाने के लिए कर दिया है कि हमने भूखों, गरीबों के लिए इंतजाम कर दिया। केवल इतना है। लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें न किसानों के लिए कुछ है और न गरीबों के लिए है। गरीबों की संख्या ही बता दी जाए कि कौन कौन गरीब हैं? उत्तर में ही बता दें कि ये-ये लोग गरीब हैं। इनकी संख्या इतनी है। 1997 में हमने बता दिया कि इतने गरीब हैं और अब 16 साल के बाद कितने गरीब हैं? गरीबों की गणना की ही नहीं गयी है। किसको बांटा जा रहा है? यह बात इस बिल में स्पष्ट नहीं बताई गई है। खाद्यान्न भंडारण पर इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है और मैं एक राय दे रहा हूं, मेरा यह सुझाव है कि खाद्यान्न के भंडारण से लेकर वितरण तक खर्च केन्द्र सरकार देगी। यह मत करना कि किसानों को दे दो, गरीबों को दे दो और उसमें किराया, भाड़ा, आने-जाने का आप हिसाब-किताब करके पचास पैसे बढ़ाकर आप कर दो। यह सारा का सारा खर्च सरकार को ही उठाना पड़ेगा।

(m2/1555/sk-snb)

यह कहीं बिल में नहीं है कि खर्च कौन उठाएगा। गोदाम में भरा जाएगा, गोदाम से ले जाएंगे, कहां जाएगा, कैसे बंटेगा, इसका खर्च कौन देगा? यह कहीं स्पष्ट नहीं है।

मेरी राय है कि आपके लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। इससे आपको मदद मिलेगी, कुछ सुझाव आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सोनिया जी सब मुख्यमंत्रियों को बुलाकर राय लेकर इसे पास कराएं। मेरी राय है कि यह बिल तब तक रोका जाए।

(इति)

Comment [a21]: ctd by m2

Comment [r22]: Sh Mulayam Singh cd

1555 बजे

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं खाद्य सुरक्षा बिल की चर्चा में सब नेताओं की बात सुन रहा था। खास तौर से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी को सुन रहा था, मैं उन्हें बधाई दूंगा कि गरीबों के हित में यह बिल लाया गया है। खास तौर से वे गरीब जो गांवों और देहातों में रहते हैं, जो अंग्रेजी नहीं हिंदी भाषा समझते हैं और आपने हिंदी में भाषण देकर निश्चित रूप से उन लोगों के मुंह पर ताला जड़ने का काम किया है जो हिंदी में वोट मांगते हैं और अंग्रेजी में भाषण देते हैं। मैं समझता हूं समापन भाषण हिंदी में होता तो और भी अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदया, खाद्य सुरक्षा के बिल में इतनी देरी का कारण क्या है? पहले कई दशकों में नारा लगाया जाता था "यह आजादी झूठी है, इस देश की आधी आबादी भूखी है।" तब से लेकर अब तक तमाम सरकारें आई और गई लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जो गरीब का मौलिक अधिकार है, मुहैया नहीं करा पाई हैं। गरीबी का कारण क्या है? आखिर लोग क्यों गरीब हैं? हम क्यों गरीब की परिभाषा परिभाषित नहीं कर पाए हैं? जब इस मुल्क में गांव से लेकर शहर तक रहने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो वे गरीब क्यों हैं? हम अमीर क्यों है? इस अंतर को कम करने के लिए अगर अब तक प्रयास किया होता तो मैं समझता हूं कि इस बिल की जरूरत न होती। जोशी जी बोल रहे थे मैं सुन रहा था, वे लोग जिनके पास खेत नहीं है। मैं समझता हूं कि गरीबी का पहला कारण सामाजिक है। हम सदन में आर्थिक भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं लेकिन सामाजिक भ्रष्टाचार आजादी से लेकर अब तक हुआ है, इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। अगर इस पर चर्चा होती तो शायद गरीबी हमारी नजर के सामने होती, उसे दूर करने का कारण होता। पहले सामाजिक कारण था कि इस देश में रहने वाला गांव का गरीब झोंपड़ियों में रहता है, गरीब है। वह गरीब आज दो वक्त की रोटी का मोहताज़ है, है, दूसरे के आगे हाथ फैलाएगा। (n2/1600/bks-rbn) हाथ फैलाकर जायेगा कि हमें खाने के लिए अनाज चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे गरीब अपमानित होगा, उसका मजाक उड़ाया जायेगा, चूंकि सामाजिक कारण में कारण था, लेकिन जब वह कानून के दायरे में आ जायेगा तो वह गरीब आदमी अपने आपको अपमानित और ठगा हुआ महसूस करेगा कि मैं इस दायरे में आता हूं। इसलिए मुझे इस बिल का कानून का फायदा उठाना है।

Comment [r23]: Cd by n2

Comment [B24]: (Sh.Dara Singh Chauhan cd.)

अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि अब तक जो सरकारें रही हैं, चूंकि वह गरीब है, अगर हमें बुखार हुआ तो हमें पैरासिटामोल का टैबलेट दे दी कि बुखार उतर जायेगा, थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन

पूरा डायग्नोसिस, जो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि रोग का कारण क्या है, आज बुखार है, कल कोई भयंकर रोग हो सकता है, जानलेवा बीमारी हो सकती है, उस बीमारी को जानने के लिए हमने ईमानदारी से अगर प्रयास किया होता तो शायद आज इस देश में गरीबों की संख्या खोजने पर भी नहीं मिलती।

आज जो स्कीम्स बनाने वाले लोग हैं, उनके अनुसार 166 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलेगा, यानी कि एक टाइम मिलेगा। उसे यदि 80-85 ग्राम मिल जायेगा तो उससे उसका क्या होगा। कौन लोग ये कानून बना रहे हैं, इस तरीके की स्कीम्स कौन लोग बना रहे हैं? ये वे लोग हैं, जिनका इससे कुछ लेना-देना नहीं है। वे स्लाइस, मक्खन खाने वाले लोग होंगे, जो फाइव स्टार होटलों के कमरों में बैठकर नीति बनाते हैं, जिन्हें गरीबी का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने गरीबी को करीब से नहीं देखा। 166 ग्राम, 155 ग्राम जो मिडडे मील में हम बच्चों को देते हैं, वह किसान, मजदूर, ट्राइबल, अनुसूचित जाति, ओबीसी का व्यक्ति है या खेत-खलिहान में काम करने वाला, पहाड़ों पर काम करने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, जो बहुत मेहनत करता है, इससे उसके लिए दो वक्त भरपेट रोटी की व्यवस्था भी हो पायेगी या नहीं, मुझे इस पर शंका है। हमारे यहां जो कमियां हैं, हमारे पीडीएस सिस्टम में वहां से लेकर गोदाम के बीच में जिस लीकेज की बात खुद श्रीमती सोनिया जी ने स्वीकार की है, मैं समझता हूं कि इस पर भी हमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि यह गरीबों तक पहुंच पाये। इसके पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले जो आदेश दिया था कि इस देश में जो अनाज सड़ रहा है, वह गरीबों तक पहुंचना चाहिए, वह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके बाद हम कानून बनाकर इसे देश में ला रहे हैं, अगर ईमानदारी से इसे हम लोगों तक पहुंचा पायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस बिल को लाना सार्थक होगा। हम इसे पीडीएस सिस्टम के माध्यम से ले जायेंगे और दूसरी एजेन्सी के द्वारा ले जायेंगे, मैं समझता हूं कि इसके लिए जो अतिरिक्त गोदामों की जरूरत होगा, उनके लिए कहां से व्यवस्था होगी, यह बात इस बिल में स्पष्ट नहीं है।

महोदया, मैं इस बिल का समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा कि इस देश में रहने वाला जो गरीब है, जब इसमें लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेशों पर छोड़ा जायेगा, चूंकि आज भी प्रदेश में जहां गरीब सबसे अधिक संख्या में हैं, जो लगातार अन्याय और अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी छोटी-मोटी जमीनें लूटी जा रही हैं।

Comment [B25]: (cd. by o2)